पंजाब में ड्रग्स समस्या और नारको राजनीति

कुलदीप वर्मा
शोध छात्र
रक्षा एवं स्ट्रेतेजिक अध्ययन विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

संक्षेपिका

मादक पदार्थों की तस्करी और बड़े पैमाने पर युवाओं का इसकी गिरफ्त में होना पंजाब की सबसे बड़ी सामाजिक और राजनैतिक चुनौती बन गया है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान द्वारा खरीदी गई हिरोइन की तस्करी ड्रग सिंडीकेट और आंतकवादियों के द्वारा अमृतसर के माध्यम से होती है। पंजाब के तरण तारण, गुरुदासपुर, फिरोजपुर और फजलिका जिलों और विशेषकर अमृतसर के क्षेत्र हिरोइन की तस्करी के लिये तस्करों के पंसदीदा क्षेत्र है। पंजाब में राजनीति और ड्रग्स गहराई से जुड़ा हुआ है। राजनैतिक पर्टियां चुनाव के खर्चों के लिये बहुत अधिक नशीले पदार्थों की तस्करी के पैसों पर निर्भर है और वे मतदाताओं को लुभाने के लिये दण्ड से मुक्ति के साथ नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं।

मुख्य शब्द :– पंजाब, हरोइन, तस्करी, राजनीति, ए.टी.एस., ड्रग्स, पुलिस,

प्रस्तावना–

पंजाब में मादक पदार्थों की लत का खतरनाक स्तर तक बढ़ जाने के कारण और उसका चुनाव में एक मुद्दा बन जाने के कारण हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ। राज्य के नये नेतृत्व को इस समस्या को नई रणनीतिक नीतियों द्वारा समाधान खोजना है जो राजनीतिक दिक्कतों और त्वरित सुधार पर निर्भर नहीं होना चाहिये हालांकि ऐसा लगता है कि राज्य में मादक पदार्थों के खतरों के समाधान के रास्ते में कई बड़ी बाधायें हैं।

मादक पदार्थों की तस्करी और बड़े पैमाने पर युवाओं का इसकी गिरफ्त में होना पंजाब की सबसे बड़ी सामाजिक और राजनैतिक चुनौती बन गया है। यहाँ तक की पूरे राष्ट्र के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये चुनौती है। संवेदनशील सीमावर्ती राज्य होने के कारण यह चुनौती और भी बड़ी प्रतीत होती है। नई सरकार के अस्तित्व में आते ही मार्च 2017 में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना है इसके साथ ही ए.टी.एस. और पंजाब खूफिया पुलिस साथ में मिलकर पंजाब की जेलों में बन्द आंतकवादियों और अपराधियों के गठजोड़ को तोड़ना है जो विगत कई वर्षों से मजबूत हो रहे थे। जेलों में लिये नये सुरक्षा उपाय घोषित किये गये हैं। प्रत्येक जिले में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिये जिला ईकाइया स्थापित की गई जिनका काम स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्तर पर दवाओं की तस्करी रोकना और जानकारी जुटाना है। राज्य एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि केन्द्रीय एजेंसियों जैसे एन.सी.बी., डी.आर.आई. के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाये। हालांकि ये सकारात्मक पहल है किन्तु पर्याप्त नहीं है। एस.टी.एफ के लिये यह कार्य बहुत ही जटिल है पंजाब में युवाओं मे नशे की लत को देखते हुये राज्य में मादक पदार्थों का एक बड़ा राज्य है इसलिये केवल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को तोड़ने से निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

तस्करी का नेटवर्क–

पंजाब इस नियम का अपवाद नहीं है जहाँ माँग होगी वहीं आपूर्ति होगी। पंजाब की गोल्डन क्रेंसेट अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान से निकटता राज्य को तस्करी की लड़ाई में कमजोर बनाती है। पंजाब में हेरोइन की तस्करी अफगानिस्तान के द्वारा पाकिस्तान के रास्ते की जाती है। जिस पंजाब को कभी 'रोटी की टोकरी' कहा जाता था आज वह हेरोइन की तस्करी का गंतव्य बन गया है।

अफगानिस्तान से पाकिस्तान द्वारा खरीदी गई हिरोइन की तस्करी ड्रग सिंडीकेट और आंतकवादियों के द्वारा अमृतसर के माध्यम से होती है। पंजाब के तरण तारण, गुरुदासपुर, फिरोजपुर और फजलिका जिलों और विशेषकर अमृतसर के क्षेत्र हिरोइन की तस्करी के लिये तस्करों के पंसदीदा क्षेत्र है। भारत–पाकिस्तान सीमा पर यह तस्करी उथले पानी में तैरकर, सीमा पार करके काँटेदार तारों के ऊपर से प्लास्टिक के पैकटों में अफीम, हिरोइन भरकर फेंकना और प्लास्टिक के खोखले पाइप की सहायत से होती है। हाल ही के दिनों में भारत पाक सीमा पर पुलिस और बार्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा बड़े पैमाने पर हिरोइन की जब्ती हुई है जिससे उनके ड्रग नेटवर्क के बारें में काफी जानकारी प्राप्त होती है। जिसमें पता चलता है कि ड्रग तस्करों ने जम्मू–कश्मीर और राजस्थान जैसे सीमावर्ती राज्यों से भी तस्करी प्रारम्भ हो गई है। इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण पंजाब प्रान्त में पिछले कुछ दिनों से हुई सख्ती है। हालांकि चीजें इतनी सरल नहीं होती जितनी सतह पर दिखती है। पंजाब में और इसके साथ ही पाकिस्तान में ड्रग माफिया एक अच्छी तरह से संगठित पेशेवर तरीके से ड्रग नेटवर्क का संचालन करते हैं। मौसम, स्थलाकृति, सुरक्षा बलों की तैनाती, निगरानी प्रणाली का समुचि प्रयोग और कारकों के संयोजन का सटीक विश्लेषण और व्यापक अध्ययन के द्वारा एक पूर्णतयः सुसज्जति एवं संगठित नेटवर्क द्वारा तस्करी के ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। ड्रग माफिया सभी बिन्दुओं का एक उचित डाटाबेस रखता है। जहाँ पर वे एक सफल ऑपरेशन करते हैं उन्हें उस क्षेत्र का पूरा ज्ञान प्राप्त होता है और वहाँ से पाकिस्तान के मोबाइल नेटवर्क की कनक्टविटी भी प्राप्त होती है। भारतीय और पाकिस्तानी ड्रग माफिया सामान्यतः पाकिस्तान के सिमकार्डों का प्रयोग करते हैं जिससे भारतीय सुरक्षा एजेन्सियों को उन नेटवर्क तक पहुँचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भारत–पाक सीमा पर अच्छी पक्की सड़कों की कमी भी स्थानान्तरण के लिये सुविधाजनक होता है, बाड़ में नीचे से खुदाई करके ड्रग की तस्करी की जाती है एक बार भारत में ड्रग की तस्करी भारतीय सीमा में होने के पश्चात पंजाब में परिवहन के लिये दूसरे नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें स्तरीय कूरियर कम्पनी, ड्रग पैडलर आदि शमिल होते हैं। पंजाब के बाहर भी ड्रग की तस्करी की जाती है जिसमें दिल्ली, गोवा, मनाली आदि स्थलों पर बड़ी मात्रा में ड्रग की तस्करी की जाती है। ड्रग का एक बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों के द्वारा यूरोप और उत्तरी अमेरिका को भेजा जाता है। गोल्डन क्रेंसट के अलावा ड्रग पंजाब से उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी प्रवेश करता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में अफीम की भूसी की खेती कानूनी है। जिससे तस्करों को इनके कानूनों को तोड़ने में राजनैतिक संरक्षण प्राप्त होता है।

पंजाब में, भारत ओर पाकिस्तान के बीच अंतरर्राष्ट्रीय सीमा 553 किमी0 लम्बी है जिस पर काँटेदार तार लगी हुई है और बी.एस.एफ. की कड़ी निगरानी में आधुनिक साजो सामान के साथ निगरानी की जाती है किन्तु भौगोलिक स्थिति विकट होने के कारण इसमें कई प्रकार की कठिनाइयां है। जनवरी 2016 में पठानकोट हमले के दौरान आंतकवादियों ने उथली नदी को तैर कर सीमा पार किया इस रास्ते का प्रयोग आमतौर पर ड्रग माफियों के द्वारा किया जाता है। इससे पता चलता है कि ड्रग तस्करों और आंतकवादियों का एक संगठित नेटवर्क है जो एक दूसरे पर निर्भर है। नशीले पदार्थों की तस्करी से निटपने के लिये क्रास बार्डर सहयोग लगभग नगण्य है। पाकिस्तान रेंजरो और उसके भारतीय समकक्षों के बीच आपसी समन्वय का पूर्णतया अभाव है जिससे इस नेटवर्क से निटपने में बहुत अधिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है।

पंजाब पुलिस की नारको आंतकवाद की जांच की सीमित क्षमता है, विशेषकर आधुनिक तकनीकि और वैज्ञानिक साधनों से निपने के लिये उसका रिकार्ड बहुत ही खराब है। अनुसंधान हमेशा शुरूवाती सफलता नहीं होते कभी–कभी खराब क्रियाकलापों की विशेषता होते हैं। एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत सजा की कमी और दंड में देरी भी समस्या को बढ़ा देती है। एन.डी.पी.एस. अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों के तहत पांच ग्राम हेरोइन से कम की जब्ती छह महीने की जेल तथा 10000 रू0 का जुर्माना हो सकता है इसके अलावा, संदिग्ध आसानी से जमानत ले सकते हैं, इसका लाभ उठाने के लिये ज्यादातर तस्करी छोटी मात्रा में की जाती है। पंजाब में हेरोइन की बड़ी मात्रा की तस्करी नहीं की जाती है। ज्यादातर नशीली दवाओं का प्रयोग छोटे–छोटे मात्रा के द्वारा कुरियर के द्वारा किया जाता है।

पुलिस–राजनीतिज्ञ–विक्रेता का गठजोड़–

पंजाब में राजनीति और ड्रग्स गहराई से जुड़ा हुआ है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का दावा है कि प्रमुख राजनीतिक दल ड्रग्स तस्करी के व्यापार में जुड़े हुये हैं। क्योंकि पंजाब नारको राजनीति का युग देख रहा है। इन्होंने ड्रग्स तस्करी में शामिल कुछ लोगोां की लिस्ट तैयार की थी जिसे पूर्ववर्ती सरकार को सौंपा गया था। जिसमें मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों, विधायकों, पूर्व विधायकों कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक सेवा अधिकारी और बड़ी संख्या में थानाध्यक्षों के नाम थे। कुछ गैर सरकारी संगठन भी इस सूची में शमिल थे। हालांकि राज्य सरकार चुप रहना पंसद करती थी और उम्मीद करते थे कि यह मुद्दा भी अपनी प्राकृतिक मौत मर जायेगा। किन्तु इसके बाद अनुराग कश्यप की फिल्म 'उड़ता पंजाब' जो पंजाब की ड्रग्स समस्या पर

केन्द्रित थी उसको लेकर राजनैतिक विवाद हो गया जिससे जो समस्या केवल पंजाब की सीमाओं में ही दिखती थी पूरे देश भर में पंजाब की ड्रग्स समस्या की तरह ध्यान आकर्षित हुआ। सरकार द्वारा जिस तरह से एक फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट देने से रोका गया उससे पता चलता है कि सरकार किस स्तर तक डरी हुई थी और उसको डर था कि पंजाब में पुलिस–राजनेता और विक्रेता का नेटवर्क है, उसका पता सबको चल जायेगा। जनवरी 2014 में पहलवान से पैडलर बने जगदीश सिंह ने दावा किया था कि पंजाब के पूर्व राजस्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया मल्टी ड्रग ट्रैफिकिंग रैकट में शामिल थे किन्तु राज्य स्तरीय जांच में कुछ महत्वपूर्ण नहीं निकला किन्तु लोगों को इसके बारें में काफी जानकारी प्राप्त हुई जिससे काफी जागरूकता का प्रसार हुआ जिससे समस्या से लड़ने में काफी सहायता प्राप्त होगी।

शशिकांत जो एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी है जिन्होंने यह लिस्ट राज्य सरकार को सौंपी थी उन्होंने पंजाब उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने बताया कि राजनैतिक पर्टियां चुनाव के खर्चों के लिये बहुत अधिक नशीले पदार्थों की तस्करी के पैसों पर निर्भर है और वे मतदाताओं को लुभाने के लिये दण्ड से मुक्ति के साथ नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं। शशिकांत ने दावा किया है कि पंजाब पुलिस, नशीले पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो खुफिया विभाग और सीमा सुरक्षा बल के कुछ लोग शामिल हैं। इसमें से कुछ लोगों को 2014 में गिरफ्तार किया गया। इसमें सबसे अधिक पंजाब पुलिस के लोग थे।

निष्कर्ष–

जो लोग ड्रग्स तस्करी में पकड़े जा रहे हैं वो स्थानीय स्तर के लोग हैं, बड़े आपूर्तिकर्ता लगभग पकड़ से बाहर है। नई सरकार ने यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया है कि इन आपूर्तिकर्ताओं को पकड़ने के लये कोई रणनीति बनाई है या नहीं और यह रणनीति पुरानी सरकार की रणनीतियों से कैसे अलग होगी। सार्वजनिक बयानों को छोड़कर सरकार ने स्थायी पुलिस राजनेता–विक्रेता गठजोड़ से निपटने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं दिया है और इसका कोई खाका राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय नहीं बना है। नई सरकार यदि कोई निर्णायक बदलाव करने के लिये संकल्पित है तो यह गठजोड़ अस्तित्व में नहीं रहेगा। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह है कि विभिन्न जांच और खुफिया एजेंसियों को एक समान ऐजेंडे पर सहमत करना होगा।

पाकिस्तान की भारत विरोधी नीतियों के कारण भारत ने अपने आप को सैन्य, वित्तीय, सामाजिक और राजनीतिक रुप से बहुत शक्तिशाली बना दिया है इसलिये सीधे संघर्षों की अपनी अक्षमता के कारण वह छोटे हथियारों की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी और जाली मुद्रा की तस्करी उसकी छद्म युद्ध कला की रणनीति का हिस्सा बन गई है। इसलिये पंजाब की ड्रग समस्या पाकिस्तान के हित में है। नई सरकार को पंजाब के युवाओं को ड्रग्स की लत से छुटकारा दिलाना बहुत ही बड़ी चुनौती है इसलिये रोजगार के अवसरों का सृजन, मनोरंजन गतिविधियों और खेल के लिये बुनियादी ढांच को मजबूत किया जाना बहुत ही आवश्यक है।

बी.एस.एफ और पंजाब पुलिस को क्रमशः सीमा सुरक्षा के लिये पहली और दूसरी कड़ी है। इसलिये बेहतर समन्वय के लिये जिला पुलिस अधिक्षकों और बी.एस.एफ के स्थानीय कमांडेटों के बीच नियमित बैठकें होनी चाहिये। पंजाब में सुरक्षा एंजेन्सियों के बीच सूचना साझेदारी तंत्र की कमी का इस्तेमाल ड्रग माफिया द्वारा अतीत में बहुतायत से किया जाता रहा है। इसलिये इस तंत्र को बहुत ही जल्द ही सुधारने की जरुरत है। सरकार को लम्बे समय से लंबित चल रहे ड्रग्स संबंधित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर जांच प्रारम्भ करनी चाहिये। चूंकि पंजाब और बी.एस.एफ. ने एक बड़ी संख्या में तस्करों और युवाओं को गिरफ्तार किया है। एक सरकार के आंकड़ों के अनुसार पंजाब की जेलों में ड्रग्स के आदी कैदियों को नियमित रुप से आपूर्ति मिल रही है। वे अपने रिश्तेदारों के बैंक खातों के जरिये लेनेदन करते है। इसलिये जेलों में इस सप्लाई चेन को तोड़ना भी आवश्यक है।

पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में गरीबों की बुनियादी सुविधाओं और कनेक्विटीविटी और परिवहन की कमी है। भारत–पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा तंत्र और निगरानी तंत्र में प्राथमिकता के आधार पर सुधार करना होगा।

राज्य में ड्रग्स की समस्या के कारण पंजाब के युवाओं को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। राज्य में सभी प्रकार की अवैध ड्रग्स आसानी से उपलब्ध है। स्थानीय रुप से, अंतर्राज्जीय और अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं की तस्करी एक सुसंगठित आपूर्ति नेटवर्क के माध्यम से की जाती है जिसका दायरा पंजाब के साथ बाकी राज्यों में भी फैला हुआ है। इस समस्या में शामिल जटिलताओं केा देखते हुये पुलिस और सुरक्षा एंजेसियों को 'ड्रग के खिलाफ युद्ध' केवल सुरक्षा आयामों तक की सीमित नहीं है। नशीले पदार्थों से प्रभावित युवाओं के पुर्नावास, जागरूकता कार्यक्रम, और अफीम की खेती पर रोक जिसके बिना ड्रग्स

के खिलाफ मौजूदा अभियान सफल नहीं हो सकता। इसलिये व्यापक रुप से इस मुद्दे को देखने की जरुरत है इसके लिये राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत अधिक आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *War on Drugs: Challenges for The Punjab Government, R K Arora, Vinay Kaura, Orf Issue Brief No. 176 L May 2017*

2- Punjab Opioid Dependence Survey (PODS), Conducted By Society for Promotion of Youth & Masses and National Drug Dependence Treatement Centre , AIIMS, New Delhi.

3. Outlook, 12 Oct 2012. "What percentage of Punjab Youth is addicted to drugs?" Accessed at http://www.outlookindia.com/bIogs/post/what-percentage-of -Punjab-youth -is-addicted -to-d rugs/28 73/31

4. DNA, 4 Jan 2015. "Maximum drug patients in Punjab users of opium, poppy husk, smack". Accessed at http://www.dnaindia.com/india/report-maximum-drug-patients-in-punjab-users-of-opium-poppy-husk-smack- 2049594

5. Ambekar & Tripathi (2008). Size estimation of injecting drug use in Punjab, Haryana and Chandigarh. UNAIDS, New Delhi

6. Man Aman Singh Chhina, Navjeevan Gopal, Varinder Bhatia, "Punjab's war on Drugs: Such a short, toxic journey," The Indian Express, June 11, 2016.

7. http://narcoticsindia.nic.in Narcotics Control Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India 2015

8. https://www.unodc.org United Nation Office on Drugs and Crime World drug Report 2015